भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *246
जिसका उत्तर 5 अगस्त, 2026 को दिया जाना है।
14 श्रावण, 1948 (शक)

सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देना और इलेक्ट्रॉनिकी संबंधी पारितंत्र को सुदृढ़ करना

***246. श्रीमती पूनमबेन माडम :**

क्या **इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिकी संबंधी पारितंत्र को सुदृढ़ करने के लिए उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत में सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत हुई प्रगति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए प्रदान किए गए प्रोत्साहनों और सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन पहलों के रोजगार सृजन, निर्यात और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के संबंध में संभावित प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से **(घ)** : एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

'सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देना और इलेक्ट्रॉनिकी संबंधी पारितंत्र को सुदृढ़ करना' के संबंध में दिनांक 05.08.2026 को लोक सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *246 के उत्तर में उल्लिखित विवरण पत्र

****

(क) से **(घ):** माननीय प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, सरकार ने भारत के इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए संरचित और लक्षित नीतिगत पहलों को अपनाया। इन पहलों से तैयार उत्पादों के विनिर्माण में सहायता के साथ-साथ सब-असेंबली, संघटकों और अंततः मशीनरी और उपकरणों के विनिर्माण में भी सहयोग मिला। राजकोषीय सहायता के अलावा, इन पहलों में एफडीआई सुधार, कर सुधार, श्रम सुधार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) के उपाय जैसे गैर-वित्तीय समर्थन भी शामिल हैं।

<u>इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख योजनाएं:</u>

भारत में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:

- बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना
- आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना 2.0
- इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना
- इलेक्ट्रॉनिक संघटकों और अर्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना (एसपीईसीएस)
- इलेक्ट्रॉनिक संघटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस)

संबंधित योजनाओं/पहलों के अंतर्गत दिए गए प्रोत्साहनों/सहायता का ब्यौरा www.meity.gov.in पर उपलब्ध है।

<u>इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण पर इन पहलों का प्रभाव:</u>

इन पहलों से पिछले 12 वर्ष में देश में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हुआ है, जिसे निम्नलिखित आंकड़ों से देखा जा सकता है:

#	2014-15	2025-26	टिप्पणियां
इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उत्पादन (₹)	~1.9 लाख करोड़	~13.11 लाख करोड़	7 गुना वृद्धि
इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात (₹)	~38 हजार करोड़	~4.24 लाख करोड़	11 गुना वृद्धि
मोबाइल फोन का उत्पादन (₹)	~18 हजार करोड़	~6.27 लाख करोड़	33 गुना वृद्धि
मोबाइल फोन का निर्यात (₹)	~15 सौ करोड़	~ 2.59 लाख करोड़	165 गुना वृद्धि

इन पहलों के परिणामस्वरूप, भारत मात्रा के संदर्भ में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माता बन गया है। देश वर्ष 2014 में मोबाइल फोन के शुद्ध आयातक से अब एक शुद्ध निर्यातक देश बन गया है।

भारत अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां भारत में इस्तेमाल होने वाले ~99.2% मोबाइल फोन भारत में बने होते हैं।

स्मार्टफोन, जो वर्ष 2014 में शीर्ष 100 निर्यातित पण्यवस्तुओं में शामिल नहीं था, अब वित्त वर्ष 2025-26 में भारत से निर्यात की जाने वाली शीर्ष प्रथक वस्तु के रूप में उभरकर सामने आया है।

भारत से इलेक्ट्रॉनिकी निर्यात में स्मार्टफोन, फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, पीसी, पॉप्युलेटेड लोडेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) और कई अन्य संघटक शामिल हैं।

उद्योग जगत के अनुमानों के अनुसार, भारत का इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र ~ 25 लाख रोजगार (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) का समर्थन करता है, जो औद्योगिक रोजगार के अवसर पैदा करने के मामले में क्षेत्र की बढ़ती हुई भूमिका को दर्शाता है।

<u>मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (एमपीएमएस)</u>

मोबाइल फोन विनिर्माण को और आगे बढ़ाने, घरेलू मूल्यवर्धन सुदृढ़ करने, आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को मजबूत करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 62,500 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (एमपीएमएस) को मंजूरी दी है।

<u>सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम:</u>

सेमीकंडक्टर उद्योग एक मूलभूत उद्योग है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र जैसे औद्योगिक, उपभोक्ता, रक्षा, दूरसंचार और मोटर वाहन आदि सेमीकंडक्टर पर निर्भर करते हैं। यह क्षेत्र तकनीकी नवाचार, आर्थिक विकास और रणनीतिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर परिवर्तनकारी क्षमताएं प्रस्तावित करता है।

सेमीकंडक्टर के महत्व को स्वीकार करते हुए, सरकार ने सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब्स सेमीकंडक्टर पैकेजिंग की स्थापना और भारत में डिजाइन किए गए चिप्स को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2022 में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रोत्साहनों/सहायता का ब्यौरा www.ism.gov.in पर उपलब्ध है।

सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत, सरकार ने लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपए की कुल निवेश प्रतिबद्धताओं के साथ 6 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, पंजाब, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में फैली 12 विनिर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन 12 परियोजनाओं में से तीन संयंत्रों से वाणिज्यिक उत्पादन पहले ही शुरू हो चुका है।

सेमीकॉन 2.0:

सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए निरंतर सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15.07.2026 को 1.27 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य एक आत्मनिर्भर, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितकी तंत्र स्थापित करना है। सेमीकॉन 2.0 में निम्नलिखित छह स्तंभ शामिल हैं:

क्र. सं.	स्तंभ	खंड
1	चिप्स का डिजाइन	रणनीतिक और वाणिज्यिक चिप्स
2	मशीनें और सामग्री	उपस्कर, रसायन, गैसें, सामग्री
3	और अधिक फैब स्थापित करना	सिलिकॉन, डिस्प्ले, कंपाउंड आदि
4	एटीएमपी/ओएसएटी उद्योग को और मजबूत करना	उन्नत और पारंपरिक पैकेजिंग
5	अनुसंधान एवं विकास	उन्नत प्रौद्योगिकियां
6	प्रतिभा विकास	डिजाइन और विनिर्माण प्रतिभा

******